

**इस्पात मंत्रालय**

**मांग संख्या 86**

**इस्पात मंत्रालय**

क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व	-5.12	64.09	58.97	15.00	67.95	82.95	15.00	23.48	38.48	15.00	70.62	85.62
पूँजी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	<b>-5.12</b>	<b>64.09</b>	<b>58.97</b>	<b>15.00</b>	<b>67.95</b>	<b>82.95</b>	<b>15.00</b>	<b>23.48</b>	<b>38.48</b>	<b>15.00</b>	<b>70.62</b>	<b>85.62</b>
<b>ब.अ. 2016-2017</b>												
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451	...	...	...	...	...	...	...	...	...	26.06	26.06
<b>लौह तथा इस्पात उद्योग</b>												
2. लौह तथा इस्पात क्षेत्र में शोध और विकास संवर्धन योजना	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	15.00	...	15.00
3.												
3.01 वीआरएस के कार्यान्वयन के लिए जुटाए गए ऋणों के संबंध में हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को ब्याज सब्सिडी	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	44.05	44.05
4. अन्य कार्यक्रम	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.51	0.51
<b>सं.अ. 2015-2016</b>												
5. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451	...	19.66	19.66	...	23.35	23.35	...	22.99	22.99	...	...
<b>लौह तथा इस्पात उद्योग</b>												
6. लौह तथा इस्पात क्षेत्र में शोध और विकास संवर्धन												
6.01 लौह तथा इस्पात क्षेत्र में शोध और विकास संवर्धन योजना - चल रही शोध और विकास परियोजनाएं	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6.02 कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएण्टेड इस्पात शीट और अन्य मूल्यवर्धित नवाचारी इस्पात उत्पाद (नया घटक) के लिए प्रौद्योगिकी विकास	2852	0.25	...	0.25	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	...	...
6.03 नवाचारी लोहा और इस्पात निर्माण प्रक्रिया प्रौद्योगिकी विकास (विद्यमान योजना के तहत नई	2852	1.78	...	1.78	14.00	...	14.00	14.00	...	14.00	...	...

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
परियोजनाएं)													
जोड़- लौह तथा इस्पात क्षेत्र में शोध और विकास संवर्धन	2.03	...	2.03	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	...	...	...	
7. सस्मिडी													
7.01 वीआरएस के कार्यान्वयन के लिए जुटाए गए ऋणों के संबंध में हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को ब्याज सस्मिडी	2852	...	44.05	44.05	...	44.11	44.11	...	...	...	...	...	
8. गारंटी शुल्क माफ करना													
8.01 हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	2852	...	5.18	5.18	...	5.18	5.18	...	...	...	...	...	
8.02 घटाइए - निवल प्राप्तियां	0075	...	-5.18	-5.18	...	-5.18	-5.18	...	...	...	...	...	
कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
9. बर्ड ग्रुप ऑफ कम्पनीज के तहत बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लि. को अनुदान	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
10. अन्य कार्यक्रम	2852	...	0.38	0.38	...	0.49	0.49	...	0.49	0.49	...	...	
<b>जोड़-लौह तथा इस्पात उद्योग</b>	<b>2.03</b>	<b>44.43</b>	<b>46.46</b>	<b>15.00</b>	<b>44.60</b>	<b>59.60</b>	<b>15.00</b>	<b>0.49</b>	<b>15.49</b>	...	...	...	
11. सरकारी उद्यमों में निवेश	6852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
12. वास्तविक वसूलियां	2852	-7.15	...	-7.15	...	...	...	...	...	...	...	...	
<b>कुल जोड़</b>	<b>-5.12</b>	<b>64.09</b>	<b>58.97</b>	<b>15.00</b>	<b>67.95</b>	<b>82.95</b>	<b>15.00</b>	<b>23.48</b>	<b>38.48</b>	<b>15.00</b>	<b>70.62</b>	<b>85.62</b>	
विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	
<b>ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>													
11.01 भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड	12852	...	6839.76	6839.76	...	7500.00	7500.00	...	6500.00	6500.00	...	6000.00	6000.00
11.02 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	12852	...	1625.58	1625.58	...	1801.00	1801.00	...	1428.98	1428.98	...	1678.00	1678.00
11.03 हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	12852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11.04 राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड	12852	...	3136.07	3136.07	...	3588.00	3588.00	...	3787.00	3787.00	...	3964.00	3964.00
11.05 कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड	12852	...	8.75	8.75	...	27.00	27.00	...	3.00	3.00	...	500.00	500.00
11.06 मैगनीज ओर इंडिया लिमिटेड	12852	...	114.78	114.78	...	127.47	127.47	...	128.07	128.07	...	139.53	139.53
11.07 बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज	12852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11.08 मेकॉन लिमिटेड	12852	...	6.12	6.12	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00
11.09 एमएसटीसी लिमिटेड	12852	...	...	...	...	10.00	10.00	...	5.00	5.00	...	10.00	10.00
11.10 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड	12852	...	12.65	12.65	...	12.00	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	12.00
<b>जोड़</b>	...	<b>11743.71</b>	<b>11743.71</b>	...	<b>13070.47</b>	<b>13070.47</b>	...	<b>11869.05</b>	<b>11869.05</b>	...	<b>12308.53</b>	<b>12308.53</b>	

ग. योजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट सहायता											
		आं. व. वा. सं.	जोड़	जोड़	आं. व. वा. सं.	जोड़	जोड़	आं. व. वा. सं.	जोड़	जोड़	आं. व. वा. सं.	जोड़	
1. लोहा और इस्पात उद्योग	12852	-5.12	11743.71	11738.59	15.00	13070.47	13085.47	15.00	11869.05	11884.05	15.00	12308.53	12323.53

1. **सचिवालयः** प्रावधान इस्पात मंत्रालय के सचिवालय व्यय को पूरा करने के लिए हैं।

2.01. **लोहा और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास का संवर्धन:** इस स्की म के तहत राष्ट्रीय महत्व की आर एंड डी परियोजनाओं पर कार्रवाई करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

3. 3.01 - हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कनस्ट्रक्शन लिमिटेड: स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वीआरएस) के क्रियान्वयन के लिए बैंकों से प्राप्त ऋणों पर व्याज का भुगतान करने हेतु एचएससीएल ने वर्ष 1999 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित पुनर्संरचना योजना के अनुसार वीआरएस के निधियन हेतु तीन वाणिज्यिक बैंकों से आवधिक ऋण प्राप्त किया है, नामशः एसबीआई- 209.82 करोड़ रूपए, विजया बैंक- 50.00 करोड़ रूपए और आईसीआईसीआई बैंक- 258.54 करोड़ रूपए, जो कुल मिलाकर 518.36 करोड़ रूपए बैठता है। इन ऋणों के लिए मूलधन और उस पर अर्जित व्याज दोनों के लिए सरकारी गारंटी प्रदान की गई थी।

4. **अन्या कार्यक्रमः** इनमें लोहा एवं इस्पात विकास आयुक्त(डीसीआई एंड एस), कोलकाता, जो कि मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है, के कार्यालय संबंधी स्थापना व्यय तथा सुप्रसिद्ध धातुकर्मियों को वार्षिक आधार पर दिए जाने वाले पुरस्कार के प्रावधान शामिल हैं।

11. **सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश:** इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा विभिन्न पूंजीगत स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए प्रावधान किया गया है। वीई 2016-17 में कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया गया है। सभी पीएसयू अपने-अपने आईईवीआर से अपने- अपने पूंजीगत खर्चों को पूरा करेंगे। ब्यौरा निम्नवत है:

11.01. **स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेडः** इसके 5 एकीकृत इस्पात संयंत्र हैं जो बर्नपुर, बोकारो, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में स्थित है तथा एलॉय इस्पात संयंत्र दुर्गापुर और सेलम में स्थित है। दिनांक 16.2.2006 से इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (इस्को), सेल की सहायक कंपनी, का सेल में विलय कर दिया गया है तथा इसे इस्को स्टील प्लांट (आईएसपी) नाम दिया गया है। महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड, जो फैरो मिश्र का उत्पादन करती है और जो कि पूर्व में सेल की सहायक कंपनी थी, का सेल के साथ विलय कर दिया गया है और इसका नाम अब चन्द्रपुर फैरो एलॉय प्लांट रखा गया है। भारत रिफैक्ट्रीज लिमिटेड (बीआरएल), जो कि इस मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है, का विलय भी सेल के साथ किया गया है और इसका नाम अब सेल रिफैक्ट्रीज लिमिटेड (एसआरयू) है। सेल संयंत्रों/इकाइयों और इसकी सहायक कंपनियों के योजना परिव्यय को सेल के आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से पूरा किया जा रहा है।

(i) भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए 1535 करोड़ रूपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 1388.00 करोड़ रूपए संयंत्र के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए हैं। शेष परिव्यय कोक ओवन बैटरी-9, रावघाट खान के विकास, वीएफ-4 के स्टोव के अपग्रेडेशन जैसी स्कीमों तथा अन्य चल रही, पूर्ण की गई एवं नई स्कीमों के लिए है।

(ii) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिए 400.00 करोड़ रूपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है, जिसमें से संयंत्र के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के लिए 291.00 करोड़ रूपए निर्धारित किए गए हैं। इस परिव्यय में शामिल अन्य स्कीमों में कोक ओवन बैटरी (सीओबी) संख्या 5 का पुनर्निर्माण, व्हील के अनिवार्य हाईड्रोलिक्स के साथ प्रेस इलेक्ट्रॉनिकी का अपग्रेडेशन, नई रोटरी हियर्थ फर्नेस की स्थापना तथा अन्य चल रही, पूर्ण की गई एवं नई स्कीमों शामिल हैं।

(iii) राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिए 1240.00 करोड़ रूपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। परिव्यय में शामिल प्रमुख स्कीम में आरएसपी का विस्ताहर (566.00 करोड़ रूपए) शामिल है। अन्य स्कीमों में नई हॉट स्ट्रिप मिल (एचएसएम) की स्थापना, ब्लाकस्टा फर्नेस-1 का अपग्रेडेशन, सीओबी-3 का पुनर्निर्माण तथा अन्य चल रही, पूर्ण की गई एवं नई स्कीमों शामिल है।

(iv) बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए 410.00 करोड़ रूपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है, जिसमें से संयंत्र के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के लिए 186.00 करोड़ रूपए निर्धारित किए गए है। अन्य स्कीमों में सीओबी संख्या-7 का पुनर्निर्माण, स्टील मेल्टिंग शॉप (एसएमएस)-1 का आधुनिकीकरण तथा अन्य 3 चल रही, पूर्ण की गई एवं नई स्कीमों शामिल है।

(v) इस्को स्टील प्लांट के लिए 990.00 करोड़ रूपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। इसका मुख्य भाग आईएसपी के आधुनिकीकरण एवं विस्तार (969.00 करोड़ रूपए), सीओबी संख्या 10 के पुनर्निर्माण के लिए है और शेष राशि अन्य चल रही, पूर्ण की गई एवं नई स्कीमों के लिए है।

(vi) मिश्र इस्पात संयंत्र के लिए 10.00 करोड़ रूपए का परिव्यय कई पूरी हो चुकी स्कीमों, चल रही स्कीमों तथा नई स्कीमों के लिए है।

(vii) सेलम इस्पात संयंत्र के लिए 15.00 करोड़ ₹0 का परिव्यय आवंटित किया गया है। इस परिव्यय का अधिकांश हिस्सा एसएसपी के विस्तार (7.00 करोड़ रूपए) के लिए तथा शेष राशि चल रही, पूर्ण की गई और नई स्कीमों के लिए है।

(viii) 244 करोड़ रूपये का परिव्यय कच्चा माल प्रभाग के लिए आवंटित किया गया है। परिव्यय का अधिकांश हिस्सा पैलैट संयंत्र (114 करोड़ रूपये) के साथ गुआ में उत्पादन क्षमता की वृद्धि के लिए है। अन्य बड़ी स्कीमों में मेघाहाताबुरु एवं बोलानी खानों का विस्तार कार्य के रूप में है तथा शेष धनराशि चल रही, पूर्ण की गई और नई स्कीमों के लिए है।

(ix) शेष 155.00 करोड़ रूपये के परिव्यय का प्रावधान विश्वेश्वरया आयरन एंड स्टील लि0 (15.00 करोड़ रूपये), सेल की केंद्रीय इकाइयों (51.00 करोड़ रूपये के संयुक्त उद्यम के माध्यम से निवेशों समेत 110 करोड़ रूपये), चंद्रपुर फैरो अलॉय प्लांट (30.00 करोड़ रूपए) की विभिन्न चल रही और नई स्कीमों/परियोजनाओं तथा अनुसंधान कार्य के लिए किया गया है।

11.02. **राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेडः** आरआईएनएल के अधीन विशाखापटनम स्टील प्लांट भारत का पहला तट आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र है। 3 एमटीपीए क्षमता की इस परियोजना की सभी यूनितों को कमिशन कर लिया गया था और ये जुलाई, 1992 से प्रचालन कर रही हैं। लगभग 12300 करोड़ रूपये की लागत से 6.3 एमटीपीए क्षमता तक का विस्तार अप्रैल, 2015 में कमिशन कर लिया गया है।

आरआईएनएल ने विद्यमान यूनितों की स्थिति को मजबूत करने के लिए तथा साथ ही तरल इस्पात क्षमता को 7.3 एमटीपीए तक बढ़ाने के लिए कई आधुनिकीकरण परियोजनाएं भी आरंभ की हैं। ब्ला स्टर फर्नेस-1 के श्रेणी-1 के वृहत मरम्मत कार्य जुलाई 2014 में पूरे कर लिये गये हैं। अन्य बड़ी यूनितों यथा ब्लास्टर्ड/ फर्नेस-2, सिंटर प्लांट और स्टील मेल्ट शांप कनवर्टरों की वृहत मरम्मत/आधुनिकीकरण कार्य शुरू कर लिये गये हैं और इनके उत्तरोत्तर रूप से वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही तक पूरा हो जाने की प्रत्याशा है। वृहत मरम्मत के पश्चात हॉट मेटल के उत्पादन में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए एसएसएस-2 में एक अतिरिक्त कनवर्टर और कास्टर की स्थापना की जा रही है तथा वर्ष 2016-17 तक कमिशन होने की आयोजना की गई है।

आरआईएनएल के उपरोक्त कार्यों और अन्य एएमआर स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2015-16 हेतु 1402.00 करोड़ रूपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2015-16 के लिए ओएमडीसी लि. और वीएसएलसी लि. का योजना परिव्यय क्रमशः 26.98 (2015-16 का आरई) करोड़ रूपये और शून्य है। इसके अतिरिक्त, आरआईएनएल के उक्त कार्यों तथा अन्य एएमआर/आर एंड डी स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2016-17 के लिए 1350 करोड़ रूपए के परिव्यय की आयोजना की गई है। समस्त परिव्यय को आईईवीआर से पूरा किया जाता है।

11.03. **हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेडः** आधुनिक इस्पात संयंत्रों के पूर्ण निर्माण के लिए इस उपक्रम को वर्ष 1964 में निगमित किया गया। कंपनी ने अवसरंचना क्षेत्र में अपने कार्य का विस्तार किया है जिसमें उच्च स्तर का नियोजन, समन्वय और आधुनिक परिष्कृत तकनीक इत्यादि शामिल है। एचएससीएल के लिए किसी योजना परिव्यय का प्रस्ताव नहीं किया गया है। इस पीएसयू की पुनर्संरचना करने पर सरकार विचार कर रही है।

11.04. **एनएमडीसी लिमिटेडः** एनएमडीसी लौह अयस्क की एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है और देश में केवल यांत्रिक हीरे खान का परिचालन कर रही है। कंपनी इस्पात निर्माण और अन्य मूल्यवर्द्धित उत्पादों के क्षेत्र में भी अपने कार्यों का विस्तार कर रही है। बड़ी स्कीमों यथा छत्तीसगढ़ के नागरनार में 3 एमटीपीए क्षमता का इस्पात संयंत्र और किरन्दुल, बचेली, दौणिमलाइ एवं ग्रीनफील्डम पट्टों में खनन विकास कार्यों, एएमआर/टाउनशिप और आर एंड डी कार्यों इत्यादि के लिए 3964.00 करोड़ रूपए (बोर्ड द्वारा अनुमोदन की शर्त पर) का योजना परिव्यय निर्धारित किया गया है।

11.05. **केआईओसीएल लिमिटेडः** केआईओसीएल लिमिटेड की स्थापना ईरान को निर्यात किए जाने हेतु लौह अयस्क सांद्रणों का विनिर्माण करने के लिए की गई थी। 3 मिलियन टन सांद्रण का उपयोग करने के लिए एक पैलैट संयंत्र लगाने को मई, 1981 में मंजूर किया गया था। 116.65 करोड़ रूपए की लागत से कार्यान्वित हुई इस परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन अप्रैल, 1987 में शुरू किया गया था। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कंपनी को कुद्रेमुख में दिनांक 31.12.2005 से खनन कार्य रोकना पड़ा था।

केआईओसीएल ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए विभिन्न पूंजीगत परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 500 करोड़ रूपए का योजना परिव्यय आवंटित किया है। प्रस्तावित कुछ परियोजनाएं निम्नावत् हैं :

(i) कर्नाटक राज्य में देवदारी लौह अयस्क डिपॉजिट का विकास और ब्लास्ट फर्नेस में फार्वर्डिंग इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट इत्यादि।

(ii) लौह अयस्क डिपॉजिट के पैलैट प्लांट परियोजना विकास और सलरी पाइप लाइन की स्थापना हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन राज्य के स्वामित्व वाली पीएसयू एपीएमडीसी के साथ एनएमडीसी और आरआईएनएल की इक्विटी भागीदारी।

(iii) बिल्ट, ऑन एंड ऑपरेट (बीओओ) आधार पर बोकारो स्टील संयंत्र, सेल में 1.5 एमटीपीए पैलैट संयंत्र की स्थापना।

इस परियोजना का विकास आन्तरिक संसाधनों तथा बैंकों/वित्तीय संस्थापनों से दीर्घकालीन ऋणों के जरिये किया जायेगा।

11.06. **मॉयल लिमिटेडः** मॉयल इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के पास क्रमशः 71.57 प्रतिशत, 4.62 प्रतिशत और 3.81 प्रतिशत शेयरधारिता है। शेष 20 प्रतिशत शेयर जनता के पास है। यह देश में मैंगनीज अयस्क की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। लाभप्रदता में सुधार करने के लिए कंपनी ने इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डार्डऑक्साइड और फैरो मैंगनीज जैसे मूल्य वर्धित उत्पादों का उत्पादन शुरू किया है। बालाघाट, चिकला, केन्द्री, उकवा, मन्सा र, और गुमगांव खानों में वर्टिकल शाॅफ्ट की सिंकिंग/डीपनिंग करने, सेल और आरआईएनएल के साथ फैरो /सिलिको मैंगनीज प्लांट के लिए संयुक्त उद्यम में निवेश करने, नए क्षेत्रों का विकास एवं भूमि अधिग्रहण, पूर्वक्षणी एवं अन्वेनपण सहित वन एवं पर्यावरण की स्वीकृति तथा एएमआर स्कीमों,

टाउनशिप, अनुसंधान और विकास/व्यवहार्यता अध्ययनों आदि के लिए 139.52 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। समस्त परिव्यय को कंपनी के आईईबीआर से पूरा किया जाएगा।

11.08. **मेकॉन लिमिटेड ::** यह आई एस ओ: 9001-2008 प्राप्त देश का प्रथम परामर्शदात्री और इंजीनियरी संगठन है। यह कंपनी न केवल बेसिक इंजीनियरी, विस्तृत इंजीनियरी, परियोजना प्रबंधन आदि के क्षेत्र में परामर्शी सेवाएं प्रदान करती है अपितु इसने लौह, अलौह, तेल एवं गैस, पेट्रो-रसायन और अन्य सामान्य उद्योगों के लिए उपस्करों के डिजाइन और उनकी आपूर्ति में पर्याप्त विशेषज्ञता भी विकसित कर ली है। 5.00 करोड़ रूपए का योजना परिव्यय (आईईबीआर) में विभिन्न स्थानों में कार्यालय परिसर/अतिथि गृह का विस्तार, रद्दोबदल और वृद्धि के लिए है।

11.09. **एमएसटीसी लिमिटेड ::** यह कंपनी भारत सरकार की एक व्यापारिक कंपनी है जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी विभागों के स्क्रेप और खनिज भंडारों के निपटान/प्रापण का कार्य इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्टल/ई-कॉमर्स के माध्यम से करती है। कम्पनी निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा में वास्तविक उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार अन्य मदों के साथ-साथ स्क्रेप का आयात करती है।

कंपनी के मुख्य कार्यों को दो प्रचालनात्मक प्रभागों में बांटा गया है यथा : ई- कामर्स और व्यामपार। ई- कामर्स प्रभाग स्क्रेप, सरप्लोस स्टोदर्स, मिनरल्सक, कृषि एवं वन उत्पादों का ई-नीलामी के जरिए निपटान करता है। एमएसटीसी ने वाहनों और अन्य वाइड गुड्स यथा एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स, जो 10-15 वर्षों की लम्बी अवधि के दौरान उपयोग के पश्चात् आगे प्रचालन हेतु अप्रयोज्य हो जाते हैं, के अन्तिम कार्यशील जीवन में उनके स्क्रेप की प्रोसेसिंग के लिए पूर्ण नई पद्धति विकसित हेतु लिए यांत्रिक श्रेडिंग प्लांट की स्था ना आरंभ की है। एमएसटीसी वाहनों के अन्तिम कार्यशील जीवन के समय अनिवार्य श्रेडिंग के लिए एक कानून के क्रियान्वयन हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच), भारी उद्योग मंत्रालय, सोसाइटी आफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चर्स इत्यादि के साथ निरन्तर कार्रवाई कर रहा है। इससे देश में श्रेडिड स्क्रे ऑप का वर्तमान में होने वाले 5-6 मिलियन टन आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी और इससे परिणामतः विदेशी मुद्रा का बर्हिगमन कम होगा। भारत सरकार वर्तमान में सविसडी/एक्साइज ड्यूटी में राहत के रूप में मोटर व्हीकल के श्रेडिंग को प्रोत्साहित करने वाली स्कीम के साथ "स्क्रेपेज पालिसी" तैयार कर रही है। श्रेडिंग प्लांट की स्थापना के लिए 10.00 करोड़ रूपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है जिसकी पूर्ति आई एंड ईबीआर से की जाएगी।

11.10. **फैरो स्क्रेप निगम लिमिटेड::** एफएसएनएल, एमएसटीसी लिमि. की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है। कंपनी सेल/आरआईएनएल के इस्पात संयंत्रों तथा वीएचईएल, हरिद्वार और जेएसडब्ल्यू, डोल्बी के संयंत्रों से स्क्रेप की प्राप्ति और प्रसंस्करण का कार्य करती है। स्लैग के प्रसंस्करण और डम्पों से लोहे और इस्पात के पुनः संसाधन हेतु कंपनी को विभिन्न प्रकार के उपस्करों और आधुनिक प्रौद्योगिकी पर निर्भर होना पड़ता है। 12.00 करोड़ रूपए का योजना परिव्यय एएमआर स्कीमों के लिए है जिसे कंपनी के आंतरिक और अतिरिक्त. बजटीय संसाधनों से पूरा किया जाना है।